खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में ब्रिटेन के साथ सहयोग

1851. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के मध्य आपसी सहयोग करने की काफी गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध मे सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस मामले में की जाने वाली भावी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) ब्रिटेन से फरवरी, 1989 में आए शिष्टमंडल के साथ खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग करने की संभावनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया था।

आलू का भंडारण

1852. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सामान्यतः देश के विभिन्न भागों तथा विशेषतः उत्तर प्रदेश और बिहार में आलू भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और इसके कारण आलू उत्पादक किसानों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) इस क्षेत्र में आलू उत्पादकों की समस्याओं के निवारण, आलू की बहुआयामी उपयोग और इस वर्ष में इसके भंडारण हेतु शीतगृहों (कोल्ड स्टोरेज) की क्षमता बढ़ाए जाने की दिशा में की गई जिलेवार कार्यवाही के साथ-साथ इस संबंध में भावी योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) आलू भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण आलू उत्पादकों के सामने आ रही कठिनाईयों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उत्तर प्रदेश में शीत भंडारों का प्रबन्ध राज्य सरकार के हाथ में है। बिहार में शीत भंडारों का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार शीत भंडारों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए उदार लाइसेंस पद्धति अपना रही है। राज्य सरकार भण्डारण क्षमता को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम प्रभारों की सीमा से छूट देकर नए शीत भंडारों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दे रही है जिसेलाइसेंस धारी शीत भण्डार में कृषि उपज के भण्डारण के लिए ले सकता है। छूट 10 वर्षों की अवधि के लिए दी जाती है।

शीत भण्डारों का निर्माण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में किया जाता है। तथापि, सहकारी क्षेत्र में शीत भण्डारों को प्रोत्साहन देने तथा उनका विकास करने के लिए आम-तौर पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन॰सी॰डी॰सी॰) द्वारा उपलब्ध की गई पूरक सहायता के साथ राज्य सरकारों द्वारा तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम शीत भण्डार के निर्माण की लागत का 75 प्रतिशत भाग वहन करता है। निगम ने आलू के विपणन के लिए उत्तर प्रदेश आलू विकास तथा विपणन सहकारी परिसंघ लिमिटेड, फरूखाबाद को सहायता दी है। इसने पंजाब मार्कफैड को आलू चिप्स के उत्पादन के लिए जालन्धर में एक यूनिट की स्थापना करने हेतु एक आलू संसाधित परियोजना की भी स्वीकृति दी है।

Opening of new radio station in Andhra Pradesh

1853. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Will the Ministei of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to open more radio stations during the next two years to have more coverage in terms of population and area including the State of Andhra Pradesh; and

(b) if so, what are the details thereof alongwith the name of places to be covered under this proposal?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H K. L. BHAGAT): (a) Yes, Sir: